

गंगटोक

शुक्रवार, 17 दिसम्बर 2021

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामी

मेट्रो मैन श्रीधरन ने बीजेपी छोड़ राजनीति से लिया संन्यास 3 एक क्रिमिनल को बचा रहे हैं पीएम : प्रियंका 8

सीएम ने एसयू निर्माण का लिया जायजा

निर्माण में तेजी लाने के लिए की जा रही है पहल : गोले

जगन दाहाल

गंगटोक, 16 दिसम्बर। राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने आज अपर यांगगांग में निर्माणाधीन सिक्किम के द्वीय विश्वविद्यालय (एसयू) का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष एलबी दास, क्षेत्र विधायक राजकुमारी थापा, मंत्रिमंडल के सदस्य, सिक्किम विश्वविद्यालय के उपर्युक्त अधिकारी खरे, विश्वविद्यालय के रेजिस्ट्रार के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि सिक्किम के द्वीय विश्वविद्यालय यांगगांग में करीब 14 सालों से गंगटोक परिसर में किए गए के मकान में संचालित है। इसके कारण यांगगांग के जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब विश्वविद्यालय अपने कैपस को यांगगांग में स्थानांतरित करने की पहल शुरू कर सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को नन्देश (जिन विभागों को लैब की जस्ती ना हो) विभाग को यांगगांग में स्थानांतरित करने की सलाह दी।

उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय निर्माण कार्य सुन्दर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय स्थानांतरित करने की स्थिति अभी नहीं है। विश्वविद्यालय और राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द स्थानांतरित करने के

भ्रमण के दौरान उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गोले ने सिक्किम

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वाले को मिले कड़ी सजा : डॉ. राजू गिरी

अनुगामी का.सं.

गंगटोक, 16 दिसम्बर। राजधानी गंगटोक परिसर स्थित नए एसटीएनएम अस्पताल की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (सिक्किम) ने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा, सिक्किम के प्रवक्ता डा. राजू गिरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एसटीएनएम के स्वास्थ्य कर्मियों पर दिनदहाड़े प्राणघातक आक्रमण हुआ है। इस घटना में डा. संजय उप्रेती और एक कर्मचारी कला छेत्री गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना की पार्टी की तरफ से भर्त्सना करते हुए उन्होंने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दोनों पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाप्त की थी कामना की है।

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि राजधानी गंगटोक में विगत कुछ हफ्ते पहले भी एक घटना घटी थी, जिसमें दो व्यक्ति की एमजी मार्ग पर जान चली गई थी। सिक्किम जैसे शारीरिक राज्य में दिन प्रतिदिन घटनाओं में वृद्धि होना समाज तथा राज्य के लिए चिंता का विषय है। छोटे-मोटे विषय पर किसी का प्राण लेना यह पर्यटकों के लिए आकर्षक राज्य की छवि को धूमिल बनाने का कार्य है।

उन्होंने लिखा कि इसके लिए भाजपा राज्य सरकार तथा प्रशासन से ऐसी घटनाओं पर पूर्णविराम लगाकर सुक्षम व्यवस्था को सशक्त बनाने का अग्रह करता है। उन्होंने मांग की कि सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लाना, नियंत्रण कक्ष की स्थापना साथ ही बाजार क्षेत्रों में सुरक्षकर्मियों की गत्ती को सशक्त बनाना आवश्यक है। दूसरी ओर समाज में बढ़ते नशीले पदार्थ की अवैध व्यापार पर भी भाजपा ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए कड़ी कानून की आवश्यकता पर बल दिया।

विधायक डी.आर. थापा ने अस्पताल में हमले की निंदा की

अनुगामी का.सं.

गंगटोक, 16 दिसम्बर। अपर बुरुक विधायक डीआर थापा ने एसटीएनएम अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों पर हुए हमले की भर्त्सना की है। उन्होंने दोनों पीड़ितों डा. संजय उप्रेती और कला छेत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाप्त की कामना की है। दोनों अभी सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में उपचाराधीन हैं।

एक विज्ञप्ति में विधायक थापा ने कहा कि अस्पताल जैसे सर्वाजनिक स्थान पर दिन में इस प्रकार के आक्रमण से सभी स्तरवाले विधायकों के उपचार की व्यवस्था करने की मांग भी की। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिन्हांने व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार से क्षेत्र के बच्चों को मंच प्रदान करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम जैसे-तक प्रतियोगिता, विक्रम



सरकार इस प्रकार की निंदीय घटना को कैसे रोकेगी और भविष्य में जनता की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का कदम उठाएगी यह सरकार का तय करना होगा।

इसके अलावा, उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा सुविधा को और बेहतर करने और इस प्रकार के गंभीर और आपात रोगियों के उपचार की व्यवस्था करने की मांग भी की।

राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिन्हांने व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार से तकाल इस दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया जिससे कि राज्य की जनता फिर से खुद को सुरक्षित महसूस करें।



सरकार इस प्रकार की निंदीय घटना को कैसे रोकेगी और भविष्य में जनता की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का कदम उठाएगी यह सरकार का तय करना होगा।

इसके अलावा, उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा सुविधा को और बेहतर करने और इस प्रकार के गंभीर और आपात रोगियों के उपचार की व्यवस्था करने की मांग भी की।

राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिन्हांने व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार से क्षेत्र के बच्चों को मंच प्रदान करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम जैसे-तक प्रतियोगिता, विक्रम



कलने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को स्लाह दी कि नन्देश डिपार्टमेंट स्थानांतरित करने पर विचार करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग और क्षेत्र विधायक के कहने पर वह खुद इस निर्माण कार्य के भ्रमण में आए हैं। अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. अविनाश खरे ने कहा कि विश्वविद्यालय पक्ष भी इसे अपने मूल कैपस में स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय लिम्बु लोगों की मांग के अनुरूप जल्द ही इसे संबोधन में लिया जाएगा।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री गोले ने विश्वविद्यालय के लिए पेयजल, अस्पताल और प्रशासनिक समाज को फिलहाल 2300 विद्यार्थी और 14 सकारी कॉलेज और 4 निजी कॉलेज संबद्ध हैं, जिसमें करीब 13 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही जनकारी मिलती है कि यह विश्वविद्यालय लिम्बु लोगों और भूटिया भाषाओं में स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी की सुविधा देने वाला दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है।

उल्लेखनीय है कि 2007 से गंगटोक के विभिन्न निजी भवनों में संचालित सिक्किम के द्वीय विश्वविद्यालय में कुल 32 विभाग संचालित हैं। विश्वविद्यालय से फिलहाल 2300 विद्यार्थी और 14 सकारी कॉलेज और 4 निजी कॉलेज संबद्ध हैं, जिसमें करीब 13 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही जनकारी मिलती है कि यह विश्वविद्यालय लिम्बु लोगों की विधायक विद्यार्थी की जीत है। चार छात्रों का निष्कासन एसके-एम सरकार का एक अंहकारी निर्णय था जिसके कारण उच्च न्यायालय का छात्रों को छात्रों की आंतकवादी की विधायिका द्वारा हुआ है। इसके लिए सिक्किम नागरिक समाज सिक्किम उच्च न्यायालय का छात्रों है।

उल्लेखनीय है कि हम एक एसके-एम सरकार के अन्तर्गत राज्यपाल पर आपनी कूल 30वें विजय दिवस उत्सव के अवसर पर राजभवन परिसर में चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया एवं समान समारोह में लोगों को समानित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यपाल को राज सैनिक बोर्ड की ओर से स्मृति चिह्न प्रदान किया गया। साथ ही राज्यपाल द्वारा राजभवन के रक्कदाताओं एवं 1971 युद्ध के दिग्यांजों को समानित किया गया। स्वागत भाषण राज्यपाल के सचिव राज यादव द्वारा।

इस अवसर पर राज्यसैनिक बोर्ड के सचिव ने भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 का इतिहास प्रस्तुत किया। संस्कृति विभाग की आक्रमणीक अस्पताल घटना की विवरण है। एचएसपी लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि आज के समय में हमारे स्वास्थ्य देखभाल करने वालों की सुरक्षा सर्वोपरिधि है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को लेकर स्थानीय नागरिकों में जागरूकता पर जोर दिया।

सभा में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन वर्षों के स्वास्थ्य को ध्वनि और रुक्षता से बचाने के लिए लोकल कूद के दस सदस्यों को गिफ्टहैपर प्रदान किए गए। साथ ही राज्य सैनिक बोर्ड के दस सदस्यों का समान प्रस्तुत पत्र तथा कैश पुरस्कार देकर किया गया। राजभवन के सदस्यों में जिन्होंने राज्यसैनिक बोर्ड के दस सदस्यों को गिफ्टहैपर प्रदान किए गए।

सभा में राज्यपाल गंगा प्रसाद

विवाह की उम्म

भारत में महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 होने वाली है, इस फैसले पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लग गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस दिशा में इशारा कर दिया था। प्रधानमंत्री ने तब कहा था, सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी सही उम्र में शादी हो। इसके लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के विरिअधिकारी शामिल थे। टास्क फोर्स ने पुरजोर तरीके से कहा था कि पहली गर्भावस्था के समय किसी महिला की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। देर से विवाह होने पर परिवारों की वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत होती है। देर से शादी होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने और आजीविका चुनने का मौका मिलता है। जगजाहिर है कि बड़ी संख्या में लड़कियों की पढ़दृश शादी की वजह से बाधित होती है।

मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद भी लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 21 करने की प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, क्योंकि इसके लिए अनेक बदलाव करने पड़ेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव जरूरी हैं। कानून में बदलाव के बाद सरकारों को महिलाओं की स्थिति सुधारने पर और ध्यान देना होगा। बेशक, विगत दशकों में बाल विवाह पर काफी हद तक रोक लगी है। लड़कियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी भी समाज में एक बड़ा तबका है, जो 18 साल की न्यूनतम विवाह उम्र को नहीं मान रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 785 मामले दर्ज किए गए थे। ध्यान रहे, ये दर्ज मामले हैं, वास्तविक बाल विवाह के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। जो राज्य विकास के मामले में कुछ आगे निकल रहे हैं, वहां लड़कियां स्वयं भी बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं।

यदि विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लड़कियों का मनोबल बढ़ेगा। वे बाल विवाह जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करेंगी। परिवार व समाज को बेटी के 21 साल की होने का इंतजार करना पड़ेगा। यहां यह भी जरूर कहना चाहिए कि कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है, उसे संपूर्णता में लागू करना। परिवार व समाज को बेटियों के व्यापक विकास के लिए ज्यादा ईमानदारी से सोचना चाहिए। अब भारत में पुरुष और महिला, दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 हो जाएगी। यहां तक कि अमेरिका में भी ऐसी उच्च सीमा नहीं है। वहां साल 2000 से 2015 के बीच अवयस्कों के दो लाख से ज्यादा वैध विवाह दर्ज हुए थे। लेकिन वह अलग तरह के सामाजिक ढाँचे वाला अमीर शिक्षित देश है, जबकि भारत में सामाजिक ढाँचा दूसरी तरह का है, यहां कानून बनाकर और उसे ढाँग से लागू करके ही आदर्श समानता व समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

संपादकीय पृष्ठ

संसद से पूरे काम, व्यवहार की आस

के सी त्यागी

संविधान विशेषज्ञों द्वारा स्थापित मान्यताओं का जिस तेजी से हास हुआ है, उस पर सुधारप्रयोग कोटि द्वारा हाल में की गई टिक्कपाणी सर्वाधिक उपयुक्त है- निसंसदेह, जो संवाद हो रहा है, उसके निम्न स्तर पर राजनीतिक वर्गों को आत्मवित्तन की आवश्यकता है। ऐसे देश में, जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, वहां अलग विचार और धारणाएं तो होंगी ही। इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक वर्ग द्वारा किए जाने वाले आवश्यकता और धारणाएं तो होंगी ही। इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक वर्ग वैदिक प्रारंभ होते ही पाकिस्तान के विवेश मंत्री चकित हो गए, जब उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में अटल विहारी वाजपेयी को देखा। बहुत विस्मयकारी अंदाज में उन्होंने पूछा, आप यहां कैसे? वाक्पत्र वाजपेयी ने कहा कि वह भारत का पक्ष रखने के लिए यहां आए हैं। पाकिस्तानी विवेश मंत्री को आश्चर्य इस बात को लेकर था कि कांग्रेस सरकार से विपरीत राय रखने के बावजूद कशरीर जैसे प्रश्न पर कैसे समूचा भारत एकमत हुआ? वैदिक में अटल विहारी वाजपेयी के तर्कों के सामने सभी हटप्रभ हो गए।

ऐसे ही कई रोचक प्रसंग पंडित नेहरू और डॉकर लोहिया को लेकर भी हैं। सर्वविवित है कि किस प्रकार संसंद और संसद के बाहर, दोनों जगह कटु संवाद होता रहा। नेहरू सरकार के खिलाफ पेश पहले अविश्वास प्रस्ताव पर लोहिया ने कटु प्रहार किए, खासकर आर्थिक और विवेश नेतृत्व में दर्ज है। पाकिस्तान समय-समय पर कश्मीर पर शहर उड़ा रहा है। एसे ही एक उदाहरण का उल्लेख भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी की ताजा पुस्तक में दर्ज है। पाकिस्तान समय-समय पर कश्मीर पर शहर उड़ा रहा है।

ऐसे ही कई रोचक प्रसंग पंडित नेहरू और डॉकर लोहिया के तर्कों के सामने सभी हटप्रभ हो गए। एसे ही कई रोचक प्रसंग पंडित नेहरू और डॉकर लोहिया को लेकर भी हैं। सर्वविवित है कि किस प्रकार संसंद और संसद के बाहर, दोनों जगह कटु संवाद होता रहा। नेहरू सरकार के खिलाफ पेश पहले अविश्वास प्रस्ताव पर लोहिया ने कटु प्रहार किए, खासकर आर्थिक और विवेश नेतृत्व में दर्ज है। एसे ही एक उदाहरण का उल्लेख भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी की ताजा पुस्तक में दर्ज है। पाकिस्तान समय-समय पर कश्मीर पर शहर उड़ा रहा है। एसे ही एक उदाहरण का उल्लेख भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी की ताजा पुस्तक में दर्ज है। पाकिस्तान समय-समय पर कश्मीर पर शहर उड़ा रहा है।

मेरा इस सुखद प्रयोक्षण के साथ है। पांच दशक पहले में एक युद्ध संवाददाता के रूप में इसकी प्रसव पीड़ी का साक्षी रहा हूं। मई 1971 से लेकर जनवरी 1972 तक गांधी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व विजय दर्ज की थी और अंत्याचारों और बांग्ला मुक्ति वाहिनी के अथक स्वतंत्रता संघर्ष को त्रिपुरा, कुमिल्ला, जैसार, खुलना व ढाका से मैंने करव किया था। वहां से हिंदी की विभिन्न राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखता रहता था। तब बांग्लादेश से बिल्कुल सटे अगरतला के गेस्ट हाउस में भी महीनों रहा था। आज जब देश अपनी स्वतंत्रता की अद्वितीय का अधिकारी बन चुका है, वह अपनी विवेश नेतृत्व में दर्ज है। एसे ही एक उदाहरण का उल्लेख भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी की ताजा पुस्तक में दर्ज है। पाकिस्तान समय-समय पर कश्मीर पर शहर उड़ा रहा है।

कैसे भुलाया जा सकता है,

सीमा पार के बांग्ला विस्थापितों

को उमड़ी हालों को; ऊखें-

उमड़े-टूटे-बिलाखते लोग; खून में

यह। यद्यपि नेहरू लोहिया से असहमत थे, लेकिन उनके तर्कों का मान रखते हुए उन्होंने योजना आयोग के उपायक्षम अशोक मेहता को महसूस कर प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय।

(सीपीआई) के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और अपनी चिंताओं से उन्हें अवातर कराया। मजाकिया अंदाज में वाजपेयी ने कहा, कॉर्पेरेड, इस प्रश्न को संसद में क्यों नहीं उठाते? अगले दिन वाम दलों द्वारा संसद में इस प्रश्न को उठाया गया।

ऐसे ही एक घटनाक्रम का

जिक्र आवश्यक है, जब नेपाल में

राजशाही का विरोध करते हुए

डॉकर लोहिया ने पाल द्वारा वामपाल के

पास गिरफतार कर तिहाड़ जेल भेज

दिए गए। सरदार पटेल उस समय

गृह मंत्री थे। नेहरू ने अपने सबसे

विश्वसनीय मंत्री जॉन मथाई

को लोहिया से मुलाकात के लिए

भेजा। इसको लेकर सरदार पटेल

का विरोध करते हुए उन्होंने नेहरू को

पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज

कराई, लेकिन नेहरू का जवाब

चौकाने वाला था, जब उन्होंने

सरदार पटेल को पत्र द्वारा सूचित

किया कि इंदु (इंदिरा गांधी) उस

समय अगर दिल्ली में उपस्थित ही

होती है। नेहरू को लोहिया

के लिए उन्हें भेज देते

थे। वाजपेयी के इस विवित

कार्यक्रम का दर्शन किया गया।

उन्होंने नेहरू को लोहिया

के लिए उन्हें भेज देते

थे। वाजपेयी के इस विवित

कार्यक्रम का दर्शन किया गया।

उन्होंने नेहरू को लोहिया

के लिए उन्हें भेज देते

थे। वाजपेयी के इ

पीएम मोदी आज यूपी के सांसदों से नाश्ते पर करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई सांसदों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी शुक्रवार को सुबह नाश्ते के दौरान उत्तर प्रदेश के लगभग 40 सांसदों के साथ मुलाकात कर सकते हैं।

आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री आमतौर पर अलग-अलग समूह में भाजपा सांसदों से मुलाकात करते रहते हैं। मुलाकातों की इही कड़ी के तहत प्रधानमंत्री ने बुधवार को दक्षिण भारत से आने वाले भाजपा सांसदों के साथ मुलाकात की थी। गुरुवार को उन्होंने मध्य प्रदेश के भाजपा सांसदों के साथ मुलाकात की और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं।

वैसे तो सांसदों के साथ नाश्ते पर प्रधानमंत्री मोदी की यह औपचारिक मुलाकात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के मद्देनजर इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया



जा रहा है कि नाश्ते पर प्रदेश के सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके राज्यों से जुड़े मुद्दों पर बात करने के साथ ही उन्हें राजनीति से अलग हटकर सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होने का गुरुमंत्र दिया था।

शुक्रवार को होने वाली इस मुलाकात के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा अन्य कई केंद्रीय मंत्री भी जूदू रह सकते हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को दक्षिण भारत के सांसदों के बुधवार को दक्षिण भारत के सांसदों के बुधवार को दक्षिण भारत के सांसदों के नसीहत भी दी।

भाजपा के घोषणापत्र का दावा : चंडीगढ़ पहला झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर होगा

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (एजेन्सी)। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में सत्ताखाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को उन्हीं देश का पहला झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने का बाबा किया। पार्टी ने बाबा किया कि युवाओं को अन्य घिड़डा वर्ग (ओबीसी) के लिए अक्षण के अलावा नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

सभी निमार्णों को नियमित कर हरियाणा की तरफ पर गांवों में 'लाल डोरा' की सीमा को समाप्त कर लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने की बात करते हुए घोषणापत्र में कहा गया है कि चंडीगढ़ हाइसिंग बोर्ड और एस्टेट ऑफिस से जुड़े सभी घरों, वाणिज्यिक व औद्योगिक भवनों को नियमित किया जाएगा।

घोषणापत्र में कहा गया है कि शहर की सभी व्यावसायिक, औद्योगिक और हाउसिंग सोसायटियों को रियायती दरों पर लीजिहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने से संबंधित नीति पेश की जाएगी, जबकि अनर्जित लाभ नीति को समाप्त कर दिया

गया है कि उत्तर प्रदेश में 2015 से 2021 तक नक्ती मोटर दुर्घटना दावों को दर्ज करने के संबंध में कम से कम 92 आपाराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें 28 वकील आरोपी के यथ में शामिल हैं।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि अब तक विभिन्न जिलों में कुल 92 आपाराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 55 मामलों में 28 अधिकारकों को आरोपी बनाया गया है। एसआईटी ने कहा कि 25 मामलों में अब तक 11 अधिकारकों के खिलाफ आरोपयन संबंधित निचली अदालत को भेजे जा चुके हैं।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तब को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रतिक्रिया या सुझाव सरकार की ओर से पेश हों और खिलाफ कानून के अनुसार जल्द

मामले में निर्देश जारी कर सकती है, जो पूरे भारत में लागू होंगे।

एसआईटी ने सफकी अहमद के मामले में शीर्ष अदालत के आदेश के बाद एक रिपोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अब तक संदिग्ध दावों के कुल 1,376 मामले प्राप्त हुए हैं।

पीठ ने कहा, 'हम एसआईटी के जांच अधिकारी से संदिग्ध फर्जी दावों के संबंध में विभिन्न बीमा कंपनियों से पहले से प्राप्त विकायातों की जांच में तेजी लाने का आग्रह करते हैं।

पीठ ने एसआईटी को एक और हलफानामा दखिल करने के लिए भी कहा, जिसमें बताया गया है कि किनते नामलों में चार्जरीट दखिल किए गए हैं और किनते नामलों में संबंधित माइलिस्ट्रियल कोट द्वारा आरोप दर्ज करते हैं।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि अब तक विभिन्न जिलों में कुल 92 आपाराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 55 मामलों में 28 अधिकारकों को आरोपी बनाया गया है। एसआईटी ने कहा कि 25 मामलों में अब तक 11 अधिकारकों के खिलाफ आरोपयन संबंधित निचली अदालत को भेजे जा चुके हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तब को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रतिक्रिया या सुझाव सरकार की ओर से पेश हों और खिलाफ कानून के अनुसार जल्द

मामले में निर्देश जारी कर सकती है, जो पूरे भारत में लागू होंगे।

एसआईटी की ओर से पेश वकील को सुनने के बाद पीठ ने कहा, 'हमारी राय है कि झुड़े/धोखाधड़ी दावा याचिका दायर किए जाने के खतरे को रोकने के लिए कोई और निर्देश जारी करने से पहले, हमारे पास विवरण हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अब तक संदिग्ध दावों के कुल 1,376 मामले प्राप्त हुए हैं।

पीठ ने रजिस्ट्री से कहा कि वह परिवहन मंत्रालय को पार्टी-प्रतिवादी के रूप में पेश करे और नोटिस जारी करे।

मामले में आगे की सुनवाई की तारीख 25 नवंबर तक करते हुए पीठ ने कहा, 'हम भारत के अतिरिक्त साँलिस्ट्रियल कोट दखिल किए गए हैं और किनते नामलों में चार्जरीट दखिल किए गए हैं और किनते नामलों में संबंधित माइलिस्ट्रियल कोट द्वारा आरोप दर्ज करते हैं कि वह परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से पेश हों और अदालत की सहायता करें।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि अब तक विभिन्न जिलों में कुल 92 आपाराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 55 मामलों में 28 अधिकारकों को आरोपी बनाया गया है। एसआईटी ने कहा कि 25 मामलों में अब तक 11 अधिकारकों के खिलाफ आरोपयन संबंधित निचली अदालत को भेजे जा चुके हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तब को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रतिक्रिया या सुझाव सरकार की ओर से पेश हों और खिलाफ कानून के अनुसार जल्द

अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस लड़ाकू विमान तेजस का 2400 करोड़ का सौदा



बैंगलुरु, 16 दिसम्बर (एजेन्सी)। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिन्दुस्तान एरोनाइक्स लिमिटेड (एचएएल) ने गुरुवार को यहां भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ 2,400 करोड़ रुपये के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस एमके1ए प्रोग्राम के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

रामलिंगम ने कहा, 'एलसीए तेजस एमके1ए प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हिन्दुस्तान एरोनाइक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए गुरुवार को यहां भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ 2,400 करोड़ रुपये के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस एमके1ए प्रोग्राम के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचएएल के लिए 20 प्रकार के विकास और आपूर्ति की जाएगी।

बैंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए एचए

खेती को कैमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा : पीएम मोदी

आपांद (गुजरात), 16 दिसम्बर (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि भले ही रसायन और उर्वरकों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो लेकिन अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने का समय आ गया है।

और इस दिशा में कृषि से जुड़े प्राचीन ज्ञान को ना सिर्फ़ फिर से सौखने की ज़रूरत है बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी आवश्यकता है।

प्राकृतिक खेती पर यहाँ आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समाप्त सत्र को वीडियो कॉन्फ़रेंस के माध्यम से संवेदित करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का साहान किया और कहा कि इस दिशा में नए सिरे

से शोध करने होंगे और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक सांचे में ढालना होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक

देश में खेती हुई और जिस दिशा में बह बढ़ी, वह सभी ने बहुत बारीकी से देखा है।

उन्होंने कहा, अगले 25 वर्ष का जो हमारा सफर है, वह नई आवश्यकताओं और नयी चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है।

पिछले सात वर्ष में खेती और कृषि के क्षेत्र में उड़ाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में खेती को विभिन्न चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, यह सही है कि रसायन और उर्वरक ने उत्तरी क्रांति में आज समय अतीत का अवलोकन करने और उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह

होगा।

उन्होंने कहा, इससे पहले खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकाराल हो जाएं, बड़े कदम उठाने का यह सही समय है। हमें अपनी खेती को कैमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित होंगा।

उन्होंने कहा कि खेती में उत्पयोग होने वाले खाद और कौटनाशक दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से अरबों-खरबों रुपए खर्च करके लाना होता है और इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है।

उन्होंने कहा कि यह समस्या किसानों और सभी देशवासियों की कारण होगा और अधिक ध्यान देना



सेहत से भी जुड़ी है, इसलिए सतर्क जानकारी उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने गुरुवार को कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में महामारी के कारण माने वाले 22,915 रोगियों में से किसी में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह को जबवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'राज्य में आगरा के पारस अस्पताल के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के तरपरा के कारण टाली गई।' इस विषय के साथ योगी सरकार ने विषय ने दावे को खारिज कर दिया।

कोरोना कहर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत : योगी सरकार

लखनऊ, 16 दिसम्बर (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानपरिषद को बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में ऑक्सीजन की कमी पर मंत्रियों द्वारा लिखे गए पत्र भी चूके थे? सरकार ने तो निर्देश राज्य ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने हुई। इस विषय के साथ योगी सरकार ने विषय ने दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विषय के सदस्यों को यह स्वीकार करना चाहिए कि बड़ी संख्या में हताहों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार की दवाओं और उपचार को सुनिश्चित करने की तरपरा के कारण टाली गई।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में महामारी के कारण माने वाले 22,915 रोगियों में से किसी में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह को जबवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'राज्य में आगरा के पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की क्योंकि वहाँ एक डॉक्टर का जारी गया था। वहाँ आधे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु गई है।' प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कहा, 'राज्य में आगरा के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के तरपरा के कारण टाली गई।'

वहाँ, समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक उदयवीर सिंह ने पहले कहा था, 'ज्ञात प्रदेश सरकार ने गुरुवार को जबवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'राज्य में आगरा के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के तरपरा के कारण टाली गई।'

जबवाब में मंत्री जय प्रताप ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त की जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी। उन्होंने जाना चाहा कि जब सरकार ने खुद मामले में कार्रवाई की है, तो वह सदन में 'झूका बायान' कैसे दे सकती है।

जबवाब में मंत्री जय प्रताप ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त की जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी। उन्होंने जाना चाहा कि जब सरकार ने खुद मामले में कार्रवाई की है, तो वह सदन में 'झूका बायान' कैसे दे सकती है।

जबवाब में मंत्री जय प्रताप ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त की जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी। उन्होंने जाना चाहा कि जब सरकार ने खुद मामले में कार्रवाई की है, तो वह सदन में 'झूका बायान' कैसे दे सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि क्या सरकार के पास ऐसे ही मामलों का विवर है जो उसके अपने मंत्रियों द्वारा घबराईकित किए गए थे। कहा, 'कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु गई है।' प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह को जबवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'राज्य में आगरा के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के तरपरा के कारण मृत्यु गई है।'

जबवाब में मंत्री जय प्रताप ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त की जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी। उन्होंने जाना चाहा कि जब सरकार ने खुद मामले में कार्रवाई की है, तो वह सदन में 'झूका बायान' कैसे दे सकती है।

इससे पहले, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सांसदों ने भी ऐसे शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके बाद सदन के लिए एक डॉक्टर मृत्यु के बाद भड़की हिस्सा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके बाद सदन के लिए एक डॉक्टर मृत्यु के बाद भड़की हिस्सा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके बाद सदन के लिए एक डॉक्टर मृत्यु के बाद भड़की हिस्सा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके बाद सदन के लिए एक डॉक्टर मृत्यु के बाद भड़की हिस्सा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके बाद सदन के लिए एक डॉक्टर मृत्यु के बाद भड़की हिस्सा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके बाद सदन के लिए एक डॉक्टर मृत्यु के बाद भड़की हिस्सा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें